भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2011

लीबिया पर अमेरिका-फ्रांस-ब्रिटेन के दुराक्रमणकारी युद्ध का विरोध करो!

लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ रही ट्युनीशिया, मिस्र, येमेन, बहरीन, अलजीरिया, मोरक्को, जोर्डान आदि देशों की जनता का समर्थन करो!

अरब देशों के अंदरूनी मामलों में साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी, ब्रितानी और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों की दखलंदाजी का विरोध करो!

पिछले कुछ हफ्तों से अरब दुनिया में जो जन उभार देखने को मिल रहा है, इसने जहां एक तरफ साम्राज्यवाद को, खासकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ विश्व जनता को बेहद प्रभावित किया है। ट्युनीशिया से शुरू होकर कई अन्य अरब देशों में फैली इस जन त्सुनामी से डरकर ट्युनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली, जो पिछले 23 सालों से जनता का दमन-शोषण कर रहा था तथा पिछले 30 सालों से मिस्र में राज करते आ रहे होस्नी मुबारक गद्दी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और येमेन, बहरीन, अलजीरिया, मोरक्को, जोर्डान आदि देशों में भी जन आंदोलन इसी तर्ज पर चल रहे हैं। अरब जनता चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि साम्राज्यवादियों से सांठगांठ कर दशकों से जनता पर तानाशाही चलाने वाले तमाम शासक गद्दी छोड़ दें। लाखों अरब जनता, खासकर युवा वर्ग तमाम प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए सड़कों पर आ रहा है। कई हफ्तों तक सड़कें और चौराहें जन समंदर में तब्दील हो गईं। जनता के प्रदर्शनों पर सरकारों द्वारा किए गए हमलों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। हजारों लोग घायल हो गए। अब जबकि लीबिया पर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने दुराक्रमणकारी युद्ध छेड़ दिया, तो अरब दुनिया में घटनाक्रम ने एक अहम मोड़ ले लिया।

लीबिया में गद्दाफ़ी की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए विद्रोह को दबाने के लिए लीबिया सरकार को अपने सैन्य बलों का प्रयोग करने से रोकने के नाम पर सुरक्षा परिषद ने 'उड़ान-वर्जित क्षेत्र' (नो-फ्लाई ज़ोन) का प्रस्ताव किया। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि रूस, चीन, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। वीटो अधिकार प्राप्त रूस और चीन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रस्ताव का विरोध न करने वाले इन देशों ने स्पष्ट तौर पर लीबिया पर नाटो की सैन्य कार्रवाई का परोक्ष समर्थन किया। इस हमले का खण्डन न करते हुए सिर्फ चिंता जाहिर कर मनमोहनसिंह सरकार देश और दुनिया की जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। इज़्राएल के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए दर्जनों प्रस्तावों को रद्दी के टोकरे में डालकर जब यहूदीवादी शासकों ने अनगिनत मौकों पर फिलिस्तीनियों की अंधाधुंध हत्याएं कीं, तब उस पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने जरा भी आपत्ति नहीं की थी। (बल्कि अमेरिका ने तो इज़्राएल के लिए अपने वीटो अधिकार का अंधाधुंध इस्तेमाल किया।) लेकिन लीबिया के मामले में तो इन देशों ने प्रस्ताव पर श्याही सूखी ही नहीं थी कि आनन-फानन में उस पर अमल करते हुए बमों की बारिश शुरू कर दी। कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय अभियान बताए जाने वाले इस दुराक्रमणकारी हमले के पहले ही दिन फ्रांस के 18 बमवर्षक विमानों ने कई लक्ष्यों पर 40 बम गिराए। अमेरिकी और ब्रितानी नौसेनाओं ने लीबिया की सुरक्षा व्यवस्था को लक्ष्य बनाकर कई क्रूज़ मिस्साइलों का प्रयोग किया। अमेरिकी वायुसेना के 18 बी-2 विमानों ने 100 से ज्यादा मिस्साइलों का प्रयोग किया। कई लक्ष्यों पर बम गिराए। गद्दाफ़ी की सेनाओं द्वारा संभावित कत्लेआम को रोकने के बहाने शुरू किए गए इस युद्ध में पिछले तीन हफ्तों में सैकड़ों नागरिक मारे गए। इस बात पर कि किनके बमों से मारे जाएंगे, लीबियाइयों की जानों (मौतों) की कीमत बदल जाएगी, ऐसा दुनिया को यकीन दिलवाने की हरकत से ज्यादा घटियापन और कुछ नहीं हो सकता! मीडिया को खुद ही कहना पड़ा कि मारे गए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल साम्राज्यवादियों के मुखपत्र की तरह काम करने वाला मीडिया सच्चाइयों को तोड़-मरोड़कर गलत सूचनाओं का प्रसार कर रहा है। इस दुराक्रमणकारी युद्ध में मीडिया ने फिर एक बार अपने वर्गीय स्वभाव का परिचय दिया है।

खुद को निष्पक्ष संगठन बताने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों की कठपुतली के रूप में इस मौके पर फिर एक बार साफ तौर पर साबित हो गई। उसके महासचिव बानकी मून ने खुद को अमेरिका के पैरों के पास पूंछ हिलाने वाले कुत्ते के रूप में साबित किया। जब दिसम्बर 2008 में गाज़ा पर इज़्राएल ने अमानवीय हमले किए थे जिसमें 1,417 फिलिस्तीनी - जिनमें अत्यधिक बच्चे और महिलाएं थीं - मारे गए थे और

कई हजार लोग घायल हो गए थे; जब इज़्राएली सेना ने गैर-कानूनी ढंग से सफेद फॉस्फरस जैसे बेहद खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया था जिससे गाज़ा के कई निवासी कैंसर का शिकार हुए थे; जब उसने एफ-16 विमानों का प्रयोग कर 'टार्गेटेड किल्लिंग्स' का सिलसिला चलाया; बिजली, पानी जैसी न्यूनतम जरूरतों से भी वंचित कर जब उसने 15 लाख गाज़ा के लोगों को 'खुले जेल' जैसे हालात में जीने को मजबूर किया तब राष्ट्र संघ ने 'उड़ान वर्जित क्षेत्र' का प्रस्ताव करने का साहस नहीं किया। जब नव-नात्सी राजपक्षे सरकार ने एलटीटीई का सफाया करने के लिए विनाशकारी युद्ध शुरू कर नागरिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों पर कई टन बम गिराए थे; जब उसने युद्ध के सिर्फ आखिरी दो दिनों के अंदर 20 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दी थी; मारी गई या पकड़ी गई महिला टाइगरों पर सिंहली अंधराष्ट्रवादी सेनाओं ने अकथनीय अत्याचार किए थे तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ भी नहीं किया था। अपनी आजादी के लिए संघर्षरत कश्मीर की जनता पर दमनचक्र चलाते हुए भारत सरकार पिछले 25 बरसों से 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करती आ रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ कुंभकर्ण की नींद सो रहा था जो अब यह कह रहा है कि उसने लीबिया में गद्दाफ़ी के खिलाफ लड़ रही जनता को बचाने के लिए कमर कस ली है। शर्म है! कुल मिलाकर देखा जाए, तो दर्जनों मौकों पर अमेरिका, इज़्राएल और पश्चिमी देशों के हितों को कथित रूप से जब नुकसान पहंचता है, तब राष्ट्र संघ ने जो दिलचस्पी या तत्परता दिखाई, उत्पीड़ित देशों व राष्ट्रीयताओं के मामले में कभी नहीं दिखाई।

दरअसल लीबिया युद्ध खुद अपने आप में संयुक्त राष्ट्र संघ के 'उड़ान-वर्जित क्षेत्र' प्रस्ताव के खिलाफ है। लीबिया को अपनी वायु सेना का इस्तेमाल कर विद्रोहियों पर हमले करने से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव को लागू करने का दावा करते हुए लीबिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो अंधाधुंध बमबारी शुरू की वह दुराक्रमण के अलावा कुछ नहीं है। गद्दाफ़ी को गद्दी से उतारकर अपने लिए अनुकूल किसी शासक गिरोह को सत्ता पर बिठाकर लीबिया में मौजूद तेल संपदा को लूटना ही उनका असली मकसद है। बहरीन में जन विद्रोह को दबाने के लिए पिछले दरवाजे से साउदी अरब की सेनाओं को उतरवाने वाले ओबामा का यह कहना कि लीबियाई विद्रोहियों को बचाने के लिए ही उन्हें यह बमबारी करनी पड़ रही है, छिछोरापन की पराकाष्ठा है। अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आए दिन अंधाधुंध ड्रोन हमले करते हुए सैकड़ों लोगों की जानें ले रहे 'नोबेल शांति पुरस्कार' से नवाजे गए इस रक्त-पिपासू को दरअसल जनता के प्राणों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। साउदी अरब, येमेन, जोर्डान आदि देशों में दलाल शासकों के खिलाफ जिनका वे अब तक समर्थन करते रहे, संघर्षरत जनता को सशस्त्र बलों द्वारा गोली मार देने पर भी चुप्पी साधने वाले पश्चिमी देशों का यह कहना कि गद्दाफ़ी को सत्ता से हटा देना चाहिए, उनके दोगलेपन का साफ सबूत है। सोलह आणे की साम्राज्यवादी दोहरी नीति है!

पश्चिमी साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी से सांठगांठ करने वाले दलाल शासक - टुनीशिया का राष्ट्रपति बेन अली, मिस्र का राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, येमेन का राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह, बहरीन का अमीर इसा अल खलीफा, जोर्डान का राजा अब्दुल्ला वगैरह - कई दशकों से अपने-अपने देशों में तानाशाही चला रहे हैं। नाम के वास्ते चुनाव होने पर भी उसमें कितना फर्जीवाड़ा होता होगा इसे समझने के लिए बस टुनीशिया का एक उदाहरण काफी है - राष्ट्रपति बेन अली को हर दफे 97 से 99 प्रतिशत वोट मिलते थे?! जनता को किसी भी प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं हैं। पुलिस व खुफिया अमले जनता की हर गतिविधि को नियंत्रित करते हुए दमन करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का विरोध न उठने पाए। इन सभी देशों में बेरोजगारी का तांडव जारी है। मिसाल के तौर पर येमेन में 40 प्रतिशत बेरोजगारी है। दूसरी ओर यहां के शासकों को तेल स्रोतों पर मालिकाना है जिसके फलस्वरूप उन्होंने अनगिनत संपदाएं इकट्ठी कर रखी हैं। अरबों डॉलर का धन विदेशी बैंक में छुपाकर रखा है। टुनीशिया से भागते-भागते बेन अली अपने साथ डेढ़ टन सोना भी ले उड़ा जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक-एक तानाशाह ने जनता को लूटकर कितना धन इकट्ठा किया होगा। दूसरी ओर 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाले संकट का असर भी अरब देशों पर पड़ रहा था जिससे जनता अकथनीय मुश्किलों से परेशान है। आबादी का आधा से ज्यादा हिस्सा रोजाना दो डॉलर से कम आमदनी पर दुभर जिंदगी जी रहा है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के तहत इन देशों के तानाशाह अल कायदा को कुचलने के नाम पर जन धन का अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। येमेन ने 75 करोड़ डॉलर पर आतंकवाद-विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर जन धन का इस तरह दुरुपयोग करना भी जनता को नागवार गुजरा। अभी तक धर्म के नाम से तथा शिया और सुन्नियों बीच तथा विभिन्न कबीलों के बीच मौजूद अंतरविरोधों का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादियों ने इन तानाशाहों का हर तरह से समर्थन किया। और जनता पर उनके शोषण, उत्पीड़न समेत सभी दमनात्मक कदमों का समर्थन किया। लेकिन जन उभार की तीव्रता को भांपकर इन बूढ़े घोड़ों का पिंड छुड़ाकर नए घोड़ों को तलाश लेना बेहतर समझा। चुपके से बेन अली और मुबारक को सत्ता से हटवाकर वहां के सैन्य जनरलों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करवा दिया। वहीं दूसरे देशों में पश्चिमी देश अभी भी शासकों के ही पक्ष में खड़े हैं। 22 अरब देशों का गठबंधन अरब लीग इस पूरे संदर्भ में पश्चिमी देशों के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। अरब राष्ट्रवाद या अरब जनता की साम्राज्यवाद-विरोधी आकांक्षाओं का वह जरा भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।

जनता की जनवादी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले तथा तमाम जनता को एकजुट कर साम्राज्यवाद का मुखर विरोध करने वाले शासक ही अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं और अपने देश की सम्प्रभुता को टिकाए रख सकते हैं। जनता पर तानाशाही चलाने वाले शासक, चाहे वह गद्दाफ़ी हो या फिर कोई और, साम्राज्यवाद से समझौताहीन संघर्ष नहीं कर सकते। जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े नहीं रख सकते। अपार तेल संसाधनों से समृद्ध पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका पर अपना दबदबा कायम करने के लिए साम्राज्यवादी शुरू से कई साजिशों, षड़यंत्रों और दुराक्रमणकारी युद्धों को अंजाम देते आ रहे हैं। ऐसे तानाशाहों का जो उनके सामने घुटने टेकते हुए उनके हितों को तवज्जो देते हैं, वे समर्थन करते हैं। ऐसे तानाशाहों के प्रति जिनके बारे में वे समझते हैं कि उनके हितों को कहीं न कहीं नुकसान कर सकते हैं, वे 'यूज़ एण्ड थ्रो' (इस्तेमाल करो और फेंक दो) वाली नीति लागू करते हैं।

अरब देशों की जनता से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान :

अरब देशों की जनता को चाहिए कि वह तानाशाहों और साम्राज्यवादियों के खिलाफ अपने आंदोलनों को दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखें। साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा इन आंदोलनों का अपहरण करने की कोशिशों का मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। सत्ता से हट चुके तानाशाहों का स्थान ग्रहण करने वाले सैन्य परिषदों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमारी पार्टी अरब जगत् की समूची जनता को सावधान करती है कि वे उन सैन्य जनरलों से, जिन्होंने अभी तक तानाशाहों का साथ दिया था, यह उम्मीद न रखें कि वे लोकतंत्र की गारंटी कर सकते हैं। मजदूरों और किसानों समेत सभी जनवादी तबकों, मध्यम वर्ग, देशभक्त व साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों को एकजुट होना होगा। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष करने के अलावा अरब जनता के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। अरब दुनिया के घटनाक्रम ने इस सच्चाई को फिर एक बार साबित कर दिया कि उत्पीड़ित जन समुदायों की वास्तविक मुक्ति के लिए मार्क्सवादी विचारधारा का मार्गदर्शन और सर्वहारा के अग्रणी दस्ते के रूप में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बेहद जरूरी हैं। विभिन्न देशों को औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद एक जमाने के उपनिवेशवाद का स्थान लेने वाला नव-उपनिवेशिवाद कितने दूभर हालात पैदा कर सकता है, इसे अरब दुनिया की जनता ने पिछले 40-50 सालों में अपनी आंखों से देखा है। अगर नव-उपनिवेशवाद का खात्मा कर असली आजादी हासिल करनी है तो अरब जनता को अपने पैरों पर खड़े होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ दृढ़तापूर्वक लड़ना होगा। लीबिया पर अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले अमेरिकी, ब्रितानी और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के खिलाफ एकजुटता से लड़ना चाहिए। भाकपा (माओवादी) यह आशा करती है कि अलग-अलग देशों में साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त दलाल तानाशाहों के खिलाफ लड़े जाने वाले संघर्षों का ऐसा विकास हो जो साम्राज्यवाद का मुखरता से विरोध करते हों, उसकी दखलंदाजी और उसके द्वारा थोपे जाने वाले अन्यायपूर्ण युद्धों का दृढ़ता से प्रतिरोध करते हों। तभी अरब दुनिया तानाशाहों और साम्राज्यवादियों के शिकंजे से मुक्ति प्राप्त कर सकेगी।

भारत की जनता और विश्व जनता से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान :

आजादी और लोकतंत्र के लिए अरब देशों की जनता द्वारा किए जा रहे आंदोलन पूर्णत: न्यायपूर्ण हैं। इसके बावजूद भी कि आंदोलनकारी ताकतों में धार्मिक कट्टरपंथी और अन्य प्रतिक्रियावादी कुछ हद तक मौजूद हों, ये आंदोलन लोकतांत्रिक और प्रगतिशील हैं। इन आंदोलनों का तहेदिल से समर्थन करना चाहिए। अरब क्षेत्र के मामलों में साम्राज्यवादियों की दखलंदाजी तथा लीबिया पर पश्चिमी साम्राज्यवादियों द्वारा थोपे गए अन्यायपूर्ण युद्ध का एक स्वर में विरोध करना चाहिए।

- **लीबिया पर अमेरिका के नेतृत्व में जारी नाटो के अन्यायपूर्ण युद्ध को फौरन रोक दो!**
- **लीबिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार साम्राज्यवादियों को कतई नहीं है!**
- **अरब दुनिया के मामलों में साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की हस्तक्षेप भरी नीतियों का पर्दाफाश करो!**
- **अरब देशों में जारी जायज जन आंदोलनों का समर्थन करो!**

Abhay

(अभय)
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)